# मुस्लिम राष्ट्रों की महफिल में खुली भारत के ढोल की पोल

**अनिल जैन**

पुलवामा में जैश-ए-मुहम्मद के दहला देने वाले फिदायीन हमले के बाद उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान की सरजमीं से संचालित हो रहे आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी तीखी प्रतिक्रिया होगी। माना जा रहा था कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान अलग-थलग पड़ जाएगा और आतंकवादी तंजीमों पर लगाम कसने के लिए पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान (सेना सहित) पर चौतरफा दबाव बनेगा। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। यह सही है कि अमेरिका और रूस सहित दुनिया के तमाम देशों ने पुलवामा हमले की निंदा की है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को सीधे तौर पर किसी ने जिम्मेदार नहीं ठहराया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी एक सप्ताह की उहापोह के बाद जो निंदा प्रस्ताव पारित किया, उसमें पाकिस्तान का कहीं उल्लेख नहीं हुआ। ज्यादातर मुस्लिम राष्ट्र ही नहीं, बल्कि चीन भी पूरी तरह इस समय पाकिस्तान के साथ हैं। सऊदी अरब ने तो पुलवामा हमले के ठीक तीन दिन बाद ही पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर की मदद देने का एलान किया है। जिस इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) से भारत सरकार ने बहुत उम्मीद लगा रखी थी, उसने भी भारत को पूरी तरह निराश किया है। यह और बात है कि भारत सरकार अभी भी उस सम्मेलन में अपनी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की शिरकत को अपनी कूटनीतिक उपलब्धि मान कर चल रही है और उस सम्मेलन में भारत को झटका देने वाले पारित हुए प्रस्ताव को नजरअंदाज कर रही है।

पुलवामा हमले और उसके बाद पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर भारतीय वायु सेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई की पृष्ठभूमि में हुए ओआईसी के सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री को भी विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। यह पहला मौका था जब इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों के सालाना सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत को भी न्योता दिया गया था। पाकिस्तान ने भारत को बुलाने का पुरजोर विरोध किया था और अपनी मांग न माने जाने पर उस सम्मेलन का बहिष्कार भी किया। इस घटनाक्रम को भी भारत सरकार ने पाकिस्तान के मुकाबले अपनी कूटनीतिक बढ़त माना। कुछ पूर्व राजनयिकों और विश्लेषकों ने भी सरकार के सुर में सुर मिलाए। लेकिन अबू धाबी में इस महीने की शुरुआत में जब दुनिया के 56 इस्लामी देशों के इस सबसे बड़े संगठन की महफिल जमी तो उसमें कूटनीतिक मोर्चे पर भारतीय कामयाबी के ढोल की पोल खुल गई। ओआईसी ने न सिर्फ भारत की उम्मीदों को गहरा झटका दिया बल्कि एक तरह से भारत को बुरी तरह बेइज्जत भी किया।

सम्मेलन में भाग लेने पहुंचीं भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वहां न तो भारत के मन की बात कह पाईं और न ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इस्लामिक देशों से किसी तरह की मदद का भरोसा हासिल कर पायीं। सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित किया गया, वह भारत के लिए बेहद निराशाजनक रहा। प्रस्ताव में %भारतीय आतंकवाद' और कश्मीरियों को पेलेट फायरिंग से अंधा किए जाने की कड़ी निंदा की गई। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं था जब ओआईसी में कश्मीर का जिक्र हुआ। कश्मीर का मसला ओआईसी के हर सम्मेलन में उठता है, जिस पर कुछ देश भारत या पाकिस्तान का पक्ष लिए बगैर वहां की स्थिति पर चिंता जताते हैं। ज्यादातर देश पाकिस्तान का साथ देते हुए भारतीय सुरक्षा बलों पर कश्मीरियों के साथ ज्यादती करने और उनके मानवाधिकारों का हनन करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग रहा।

ओआईसी के सम्मेलन ने आधिकारिक तौर पर अपने प्रस्ताव में कश्मीरियों को %भारतीय आतंकवाद' का शिकार बताया। गौरतलब है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह पहला मौका रहा जब कश्मीर के संदर्भ में आधिकारिक तौर पर %भारतीय आतंकवाद' शब्द का इस्तेमाल किया गया। यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं है कि आईओसी ने अपने प्रस्ताव में न तो पुलवामा के भीषण हमले की निंदा की और न ही उस पर किसी तरह का अफसोस जताया। प्रस्ताव में बाबरी मस्जिद फिर से तामीर कराने की मांग भी गई। कुल मिलाकर प्रस्ताव की सारी बातें भारतीय हितों के प्रतिकूल रहीं। भारत को नीचा दिखाने वाली रहीं।

समूचे भारत ने एक स्वर में पुलवामा हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस आरोप को न सिर्फ सिरे से खारिज किया है बल्कि वह यह भी प्रचारित कर रहा है कि पुलवामा कांड खुद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाया है, क्योंकि इसी बहाने वे 2019 का चुनाव जीतना चाहते हैं। इस तरह के गंभीर आरोप-प्रत्यारोप के मद्देनजर उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ओआईसी के मंच से न सिर्फ पाकिस्तानी दुष्प्रचार का करारा जवाब देगी, बल्कि पाकिस्तान का नाम लेकर उसे पुलवामा के हमले के लिए जिम्मेदार ठहराएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में भारत को आतंकवाद से पीड़ित तो बताया लेकिन इस संदर्भ में अपने पूरे भाषण के दौरान पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। यही नहीं, उन्होंने पुलवामा हमले का तो जिक्र ही नहीं किया और इस पाकिस्तानी दुष्प्रचार को भी खारिज नहीं किया कि यह हमला खुद मोदी सरकार ने प्रायोजित किया था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि पाकिस्तान की सरजमीं से संचालित होने वाले आतंकवादी संगठनों जैश-ए-मुहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का उल्लेख करने से भी भारतीय विदेश मंत्री ने परहेज बरता।

कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसा उन्होंने सम्मेलन के आयोजकों के दबाव के तहत ही किया होगा। हां, सुषमा स्वराज की इस बात के लिए जरुर सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने वैश्विक आतंकवाद के संदर्भ में सैम्युल हंटिंगटन की %सभ्यताओं के संघर्ष' वाली अवधारणा को खारिज किया और कहा कि इस आतंकवाद का किसी सभ्यता, संस्कृति या धर्म से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने आतंकवाद को लेकर सुचिंतित भारतीय मान्यता को अभिव्यक्ति देते हुए कहा कि यह वैचारिक विकृति है, जो धर्म और संप्रदाय का सहारा लेकर अपने इंसानियत विरोधी नापाक मंसूबों को अंजाम देती है। एक तरह से उनके कहने का आशय यह रहा कि आतंकवाद को राजनयिक या सैन्य स्तर पर खत्म नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर सुषमा स्वराज का भाषण तथ्यपूर्ण कम और अकादमिक ज्यादा रहा।

बहरहाल, यह अब भी हैरानी का विषय है कि भारत सरकार ने ओआईसी को इतनी तवज्जो क्यों दी और उससे मिले न्योते को लेकर वह इतना उत्साहित क्यों थी? भारत ने हमेशा ही मजहबी आधार पर होने वाले इस तरह के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से दूरी बनाए रखने की नीति अपनाई है। इस सिलसिले में 1969 का वाकया जरुर अपवाद कहा जा सकता है, जब ओआईसी ने भारत को निमंत्रण देकर भी उस सम्मेलन में शिरकत करने से रोक दिया था। ऐसा पाकिस्तान के फौजी तानाशाह याह्या खां की तिकड़मों के चलते हुआ था। यह भारत का अपमान था, जिस पर तत्कालीन जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने इस सिलसिले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की नीति का हवाला देते हुए उस सम्मेलन में भारत का सरकारी प्रतिनिधिमंडल भेजने के सरकार के फैसले को धर्मनिरपेक्षता की नीति के विरुद्ध बताया था।

गौरतलब है कि 1955-56 में स्वेज नहर के संकट बाद काहिरा में आयोजित इस्लामी देशों के सम्मेलन में जब भारतीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का सवाल आया था तब नेहरू ने स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया था। नेहरू के इसी फैसले का जिक्र करते हुए वाजपेयी ने कहा था कि इस्लामी देशों के गुट में शामिल होने की कोशिश करके हमने संयुक्त और राष्ट्र गुट निरपेक्ष आंदोलन को कमजोर किया है, हमने अफ्रीकी और एशियाई देशों की एकता पर चोट की है और अरब देशों की एकता भी भंग की है। उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में क्षेत्रीय गुट बनाने की तो इजाजत है, लेकिन मजहबी आधार गुटबाजी की नहीं।

वाजपेयी ने ओआईसी के मोरक्को सम्मेलन में भारत को बुलाकर भी उसमें शिरकत न करने देने को इस्लामी देशों की एक चाल करार देते हुए कहा था कि उन्होंने भारत को अपमानित करने के लिए एक जाल बिछाया और भारत उसमें फंस गया। जाहिर है कि भारत के साथ जैसा 1969 में हुआ, वैसा ही अब ठीक 50 साल अबूधाबी में हुआ। तब और अब में फर्क इतना ही रहा कि तब भारत को निमंत्रण देकर भी उसे पाकिस्तानी दबाव के चलते उस सम्मेलन में शामिल नहीं होने दिया गया था और इस बार सम्मेलन से पाकिस्तान के अलग रहने और भारत के शिरकत करने के बावजूद सम्मेलन में भारत के खिलाफ सख्त प्रस्ताव पारित हुआ। यानी भारत के साथ पहले से ज्यादा अपमानजनक बर्ताव हुआ।

ओआईसी के प्रस्ताव से साफ जाहिर हुआ कि इस्लामिक देशों का नेतृत्व कश्मीर के मसले पर भारत के खिलाफ अपने संस्थापक सदस्य और इस्लामिक जगत के एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र पाकिस्तान को अलग-थलग करने के मूड में नहीं है और न ही वह उसे आतंकवाद को बढ़ावा देने का दोषी मानने को तैयार है। मोदी सरकार ने और किसी की न सही अगर अटल बिहारी वाजपेयी की ही 50 साल पुरानी नसीहत को याद रखा होता तो वह ओआईसी के फेंके गए जाल में फंसने और देश की किरकिरी कराने से बच सकती थी।

**हिटलर एक रात बर्लिन के सबसे प्रसिद्ध सिनेमा घर में गया, भेष बदलकर। ये देखने की जब मेरी तस्वीर आती है तो लोग क्या व्यवहार करते है !**

**फिल्म शुरू होने से पहले हिटलर की तस्वीर आयी तो सारे लोग खड़े हो गए और जय जयकार के नारे लगाने लगे!**

**हिटलर खड़ा नहीं हुआ और क्यों खड़ा हो वह तो खुद हिटलर था मगर ये भूल गया कि वह यहाँ हिटलर बन कर नहीं आया है !**

**सभी जय जयकार के नारे लगा रहे थे वह बहुत प्रसन्न था!**

**तभी बगल के आदमी ने जो खड़े होकर जय जयकार के नारे लगा रहा था उसको कंधे पे धक्का दिया और कहा खड़ा हो जा भाई अगर उस हरामजादे को पता चल जायेगा तो तू मुसीबत में पड़ जाएगा!**

**आज हम भी उसी दौर में जी रहे है। यदि उनके हाँ में हाँ नहीं मिलायें तो देशद्रोही और गद्दार बना दिए जाते हैं।**

## मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ दिल्ली में जुटे हजारों मजदूर

**इन्द्रा**

**3 मार्च, जब टीवी चैनल भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल बना रहे थे तब मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान के आह्वान पर देश के अलग-अलग हिस्सों से हजारों मजदूर एकजुट होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली आए हुए थे। लेकिन ये मजदूर मीडिया डिस्कोर्स से बाहर थे।**

**देशभर के कई हिस्सों से आए मजदूरों ने रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक मार्च निकला। इस मार्च में मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ने वाले ट्रेड यूनियन सेंटर आफ कर्नाटक, ओडिशा, भेल मजदूर ट्रेड यूनियन और मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान मासा सहित कई संगठन शामिल हुए।**

**यह मार्च नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा श्रम कानूनों को कमजोर करने और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के प्रयासों के खिलाफ था। सरकार द्वारा कानूनों में बदलाव कर परमानेंट नौकरी को समाप्त किया जा रहा है और ठेके की नौकरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। मजदूरों को 8 से 10,000 से ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते हैं।**

**इनकी मांग है कि 25,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी की जाए। यूनियन बनाने के अधिकार को मान्यता मिले। ठेके पर नौकरी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मजदूर भी नागरिक हैं। आंगनवाड़ी वर्कर से लेकर किसान तक नागरिक हैं मगर चुनावी चर्चा से बाहर कर दिए गए हैं।**

**मजदूरों की रैली रामलीला मैदान से शुरू हुई और संसद मार्ग पर समाप्त हुई। इसमें देश भर के करीब 20 राज्यों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।**

**इनमें गुड़गांव-मानेसर (हरियाणा), नीमराणा-जयपुर (राजस्थान), रुद्रपुर-हरिद्वार (उत्तराखंड), अहमदाबाद के मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, फार्मास्यूटिकल्स और संबंधित क्षेत्रों से कुछ सबसे बड़े श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि भी आए। सानंद (गुजरात), पुणे-मुंबई-गोवा, चेन्नई पेरुम्बुदूर से भी श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इस रैली में चाय बागान श्रमिक भी मौजूद थे, जिसमें दार्जिलिंग हिल्स-तराई-डुआर्स और च्ह मुक्ति संग्राम समिति, असम में चाई बागान संग्राम समिति शामिल थे।**

**मजदूरों की रैली में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल और झारखंड के कोयला खानों के श्रमिक भी उनकी आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए थे। हरियाणा से मनरेगा मजदूर यूनियन और निर्माण मजदूर यूनियन जैसे देश भर के ग्रामीण कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक भी वहां मौजूद थे, जैसे गुजरात और राजस्थान के सफाई कर्मचारी, रिक्शा और ठेला पुलर्स, जरी निर्माता, बीड़ी मजदूर यूनियन, निर्माण मजदूर यूनियन, आंगनवाड़ी वर्कर्स और डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन।**

**मासा के एक स्वयंसेवक ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से कहा, आज, नवउदारवाद का दौर है और विशेष रूप से वर्तमान शासन फासीवादी ताकतों द्वारा समर्थित है, देश के मजदूरों पर कहर बरपा रहा है। हम श्रमिकों के शोषण, दमन और अपराधीकरण को देखते हैं, बेरोजगारी का दौर है और न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है। ऐसे समय में जब चुनाव को देखते हुए युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है तो मजदूरों को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया है ऐसे में सरकार को चेताने के लिए रैली की जरूरत थी।**

**मासा पूरे देश में संघर्षरत श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों का एक संयुक्त मंच है। इंडियन सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया वर्कर्स काउंसिल, फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस सहित 13 से अधिक निकायों ने चलो दिल्ली रैली में भाग लिया। इनका कहना था कि देश मजदूर की मेहनत से चलता है लेकिन उनकी मजदूरी से किसी को वास्ता नहीं है ऐसे में हमारी मांग है कि मजदूरों को पेंशन जैसी केंद्रीयकृत सुविधाएं दी जाएं।**

**ढाई साल पहले, 26 अगस्त 2016 को, 14 श्रमिक संगठनों ने दिल्ली में एकछत्र संगठन मासा बनाने की पहल शुरू की। इन संगठनों ने एक बैनर तले इकट्ठे होकर सरकार से मांग की कि 1 जनवरी 2016 से न्यूनतम मजदूरी 22000 की जाए। अनुबंध श्रम प्रणाली को समाप्त कर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मांगों को माना जाए।**

## क्या बालाकोट में मरे आतंकवादियों की तस्वीरें आ गई हैं?

**अर्पित**

**26** फरवरी. भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की. हवा से बम गिराए और सब धुआं-धुआं कर दिया. इसके बाद से ही खबरें आने लगीं, लोग कयास लगाने लगे कि कितने आदमी थे. या यूं कहें कि कितने आतंकवादी मरे. कोई दो सौ कह रहा था कोई ढाई-तीन सौ तक जा रहा था. वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो डैमेज का सबूत मांग रहे थे. तो भाई ये रहा कंटेक्स्ट. अब खबर ये आई है कि पाकिस्तान के बालाकोट से लाशों की तस्वीरें आई हैं. तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहीं हैं.

फेसबुक पर विक्रम लाखड़ा नाम के व्यक्ति हैं. आप नहीं जानते इन्हें? कोई बात नहीं. कोई भी नहीं जानता था इनको. तो लाखड़ा जी ने अपने 'फ़ोर मिनट्स ऑफ़ फ़ेम' के लिए एक पोस्ट लिखा. पोस्ट में सामूहिक कब्रों की तस्वीर है. 3 और तस्वीरें हैं जिनमें एक कमरे में ढेरों डेड-बॉडीज़ रखी हुई हैं. इस पोस्ट को 2 हज़ार से ज्यादा लोगों ने शेयर किया है।

**क्या है सच्चाई?**

पाकिस्तान के बालाकोट में बम गिरे. इसकी पुष्टि भारतीय सेना और भारत सरकार से लेकर पाकिस्तानी सरकार, सेना और इंटरनेशनल मीडिया तक ने की है. इस बात में

कोई शंका नहीं है. लेकिन ये तस्वीरें बालाकोट की नहीं कराची की हैं. और 4 साल पुरानी हैं. हमारी पड़ताल में 27 जून 2015 की खबरों में यही तस्वीरें हमें मिलीं. ये बात तो सच है कि पाकिस्तान में सामूहिक कब्रें खोदी गईं. पर ये बम से नहीं, बल्कि गर्मी की वजह से मरे हुए लोगों के लिए थीं. 2015 में कराची में पारा 45 के पार हो गया था. ये रमज़ान के समय हुआ. ऊपर से बिजली में भी कटौती हो रही थी. इसलिए गर्मी की वजह से इतनी मौतें हुईं कि सामूहिक कब्रें खोदने की नौबत आ गई. ये खबरें हमें न्यू यॉर्क टाइम्स के साथ-साथ कई पाकिस्तान न्यूज वेबसाइट्स में भी मिलीं. इन पुरानी तस्वीरों को बालाकोट की बताकर फैलाया जा रहा है. ये पोस्ट सरासर झूठ है।

**झूठ बोलने की जरूरत नहीं**

**बालाकोट में हुई कार्रवाई सच है. इसमें कोई शक नहीं. पर कितने आतंकवादी मरे, ये साफ-साफ बताया नहीं जा सकता है. ऐसा सेना ने खुद कहा है. अब अपने दिव्य ज्ञान से मरने की तस्वीरें ले आने वाले, एक सच्ची कार्रवाई पर भी सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं. खुद को राष्ट्रभक्त समझने वाले ये 'क्यूट' लोग इनडायरेक्टली देश की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठवा रहे हैं।**